RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 08 NOVEMBER TO 14 NOVEMBER 2017 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 03 ■ अंक 11 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कच्चे तेल की कीमतें साल 2015 के बाद के उच्चतम स्तर तक
Page 2

पोलोग्राउंड औद्योगिक संगठन का कार्यालय प्रारंभ
Page 6

देश में ई-व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर
Page 7

editoria!

फिर वही काले पन्ने

काले धन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का उत्सव मनाने में जुटी केंद्र सरकार को इसे लेकर हुए एक बड़े खुलासे पर मुंह खोलना चाहिए। डेढ़ साल पहले पनामा पेपर्स का खुलासा करने वाले जर्मन अखबार 'स्यूड्यूश जाइटुंग' ने 1.34 करोड़ दस्तावेज पेश किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसे दुनिया भर के राजनेताओं, अभिनेताओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सिलेब्रिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों ने फर्जी ट्रस्ट, फाउंडेशन और कागजी कंपनियों के जरिए अपने काले धन को टैक्स अधिकारियों की नजर से छुपाकर देश का पैसा विदेश में रखने का जुगाड़ किया है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि इस लिस्ट में 714 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री और एक नामी अभिनेता समेत देश के कई जाने-माने चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। ऐक्टर अमिताभ बच्चन का नाम इससे पहले पनामा पेपर्स में भी आ चुका है, लेकिन किसी जांच का सामना करना तो दूर, उन्हें लोगों को अपना टैक्स नियमित रूप से अदा करने के लिए प्रेरित करने वाले सरकारी विज्ञापनों तक में लगातार देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और बीजेपी सांसद आरके सिन्हा के पास भी सफाई तैयार पाई गई, लेकिन वह तो देश के हर ताकतवर इंसान के पास हमेशा तैयार रहा करती है। यह सही है कि जब तक इन लोगों पर आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक इन्हें दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये लोग हमारे सिस्टम की, और इससे भी ज्यादा इस देश में रहने वाले आम लोगों की बेचारगी के जीवित प्रतीक हैं। सवाल है कि हमारी सरकार टैक्स चोरों के खिलाफ कुछ करना भी चाहती है या नहीं। पिछले मामलों को ही देखें। पनामा पेपर्स लीक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन हमारे यहां अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। उससे पहले आई एचएसबीसी की सूची पर भी नतीजा वही देखा गया। सरकार नोटबंदी और शेल कंपनियों पर प्रतिबंध को बड़ी कार्रवाई मान रही है। लेकिन इस कवायद से काले धन की सेहत पर क्या असर पड़ा, कोई नहीं जानता। फर्जी कंपनियां दोबारा खड़ी करने में देर नहीं लगती। उद्यमिता को बढ़ावा देने में जुटी सरकार इस बात पर नजर भला कैसे रख सकती है कि कौन सी कंपनी किस इरादे से बनी है। काले धन के खिलाफ लड़ाई कई देशों में लड़ी गई है और कई जगह लड़ी जा रही है। इसके तरीके खोजने के लिए आपके पास आइंस्टाइन का दिमाग होना जरूरी नहीं है। असल सवाल इरादे का ही है, जो अपने यहां न कभी पहले दिखा, न आज दिख रहा है। सरकार अगर काले धन के खिलाफ सख्ती जताना चाहती है, तो अब तक की सारी सूचियों में आए एक-एक नाम को खुद से दूर रखे।

नोटबंदी का एक साल पूरा

जानें अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ असर

नई दिल्ली। एजेंसी

1 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नोटबंदी की घोषणा की थी। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैन कर दिया था। एक ओर जहां सरकार लगातार नोटबंदी को सफल बता रही है, वहीं विपक्ष नोटबंदी को बुरी तरह फेल मान रहे हैं। नोटबंदी की सफलता और असफलता को लेकर अब भी बहस जारी है। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोटबंदी का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा।

सरकार के पास वापस आ गए पैसे

सरकार ने नोटबंदी में देश में चलन में रहे कुल कैश का लगभग 86₹ बैन कर दिया था। सरकार का दावा था कि इस कैश में बड़ी मात्रा कालेधन की है। इसलिए सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि इस कैश का काफी बड़ा हिस्सा सिस्टम में वापस नहीं आएगा और बेकार हो जाएगा। लेकिन सरकार की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब नोटबंदी के बावजूद बैन की गई करंसी का 90₹ से ज्यादा लगभग 15 लाख करोड़ रुपये बैंकों के पास वापस आ गए।

इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी

नोटबंदी कई मामलों में फायदेमंद भी रही। 2016-17 में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 25₹ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2015-16 में जहां 2.23 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे थे, वहीं 2016-17 में 2.79 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे।

संदेहास्पद खातों का पता चला

सरकार को 17 लाख से ज्यादा ऐसे संदेहास्पद खातों का पता चला जिनके इनकम टैक्स रिटर्न उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा किए पैसों के हिसाब से मेल नहीं खा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने भारी मात्रा में ऐसे लोगों नोटिस भेजा है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था

सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी को जरूरी बताया था। नोटबंदी के शुरुआती महीनों में तो कैश की तंगी के कारण लोगों ने काफी कैशलेस ट्रांजैक्शंस किए, लेकिन बाजार में कैश उपलब्ध होते ही कैशलेस ट्रांजैक्शंस में काफी गिरावट आ गई। हालांकि यह भी सच है कि पहले के मुकाबले कैशलेस ट्रांजैक्शंस में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई।

500 और 2,000 के नए नोट

आर.बी.आई. ने नोटबंदी के बाद 500 का नया नोट और पहली बार 2000 का नोट जारी किया। इन नोटों को जारी करने का उद्देश्य देश में भारी मात्रा में चलन में रहे नकली नोटों पर लगाम लगाना था। आर.बी.आई. ने इन नए नोटों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बताया था, आर.बी.आई. का दावा था कि इन नोटों की नकल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह प्रयोग भी ज्यादा सफल नहीं रहा और जल्द ही अर्थव्यवस्था में 500 और 2000 के नकली नोट भारी मात्रा में आ गए।

2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगी

सरकार ने 2016-17 के बजट में 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगी दी। ऐसा कालेधन के चलन पर रोक लगाने के लिए किया गया। वहीं 50,000 रुपये से ज्यादा का सोना खरीदने पर भी सरकार ने पैन कार्ड डीटेल देना अनिवार्य कर दिया, हालांकि इसकी सीमा बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई।

वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग की तुलना में कारोबार के लिए कहीं अधिक आकर्षक है भारत : अरविंद पनगढ़िया

वाशिंगटन। एजेंसी

शीर्ष भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत की कारोबार सुगमता रैंकिंग में सुधार काफी समय से लंबित था। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत कारोबार करने की दृष्टि से रैंकिंग की तुलना में अधिक आकर्षक स्थान है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि निवेशक वहां जाते हैं जहां माहौल सबसे अच्छा होता है, वहीं नहीं, जहां से वर्ल्ड बैंक आंकड़े जुटाता है।

उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग की तुलना में भारत कारोबार के लिए अधिक आकर्षक स्थान है। इसकी वजह यह है कि विश्व बैंक दिल्ली और मुंबई से आंकड़े जुटाता है। आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे सर्वश्रेष्ठ कारोबारी माहौल वाले राज्यों से नहीं।

इससे पहले अरविंद पनगढ़िया जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे तब कह चुके हैं कि देश के निजी क्षेत्र को अच्छे वेतन और अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करने के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि देश का मुख्य जोर रोजगार सृजन पर है। निजी क्षेत्र को बेहतर वेतन, उत्पादकता वाले रोजगार उत्पन्न करना है।

कच्चे तेल की कीमतें साल 2015 के बाद के उच्चतम स्तर तक

क्या रहा कारण, क्यों आया बदलाव

नई दिल्ली। एजेंसी

सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें जुलाई 2015 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। इसकी प्रमुख वजह साऊदी अरब के शहजादे के कारण उपजा तनाव है जिसके कारण हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ब्रेंट फ्यूचर जो कि तेल की कीमतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क है, सोमवार को 62.90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यह जुलाई 2015 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। यह जून 2017 के न्यूनतम स्तर से 40 फीसद ज्यादा है। वहीं सोमवार दोपहर के कारोबार में यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 56 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, यह भी जुलाई 2015 के बाद का उच्चतम स्तर है। डब्ल्यूटीआई का यह स्तर साल 2017 के न्यूनतम स्तर का करीब एक तिहाई ज्यादा है। साऊदी अरब के क्राउन प्रिंस (शहजादा) मोहम्मद बिन सलेम जिन्हें एमबीएस के नाम से भी जाना जाता है, ने भ्रष्टाचार विरोधी पहल के जरिए सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। इस मुहिम के चलते कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गिरफ्तार होने वाले लोगों में शाही परिवार के लोग, मंत्री और निवेशक जिसमें प्रमुख रूप से जाने माने अरबपति व्यवसाई अलावलीद बिन तलाल एवं नेशनल गार्ड के मुखिया प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्लाह शामिल हैं।

कच्चे तेल के इस उच्चतम स्तर ने सरकार के सामने फिलहाल कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

चुनौती नंबर 1: चुनावों से पहले तेल की कीमतों पर लगाम

दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे तेल का उच्चतम स्तर पर पहुंच जाना काफी गंभीर है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। साथ ही यहां पर अब उत्पाद शुल्क में कटौती का विकल्प भारी पड़ सकता है।

चुनौती नंबर 2: आयात बिल बढ़ाएगा बोझ

कच्चे तेल के महंगे होने का सीधा मतलब है आयात बिल में इजाफा होना। पहली तिमाही के दौरान तेल के आयात बिल में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे चालू खाता घाटा में भी वृद्धि होगी।

चुनौती नंबर 3: राजकोषीय प्रबंधन पर असर

कच्चे तेल के महंगे होने से आयात बिल बढ़ने के साथ साथ राजकोषीय प्रबंधन पर भी असर पड़ेगा, जिसको लेकर सरकार पहले से ही चिंतित है। वहीं इससे महंगाई दर में भी बढ़ोत्तरी संभव है।

क्या है वजह

अंतरराष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में क्रूड की कीमत और बढ़ेगी। इसके लिए दो प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि सर्दियों में आम तौर पर क्रूड महंगा होता है। सर्दियों में मांग बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में सामान्य तौर पर 10 से 30 फीसद तक की बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरी वजह यह है कि हाल ही में बड़े तेल उत्पादक देशों के बीच यह सहमति बनी है कि क्रूड उत्पादन में बड़ी कटौती की जाए। रुस की अगुवाई में कुछ देश क्रूड को महंगा करने का हरसंभव उपाय कर रहे हैं। इससे भविष्य में होने वाले सौदों पर असर पड़ा है।

क्रूड में गिरावट, सोने की चाल सुस्त

अगले 5 साल में कच्चे तेल की डिमांड 7 फीसदी तक बढ़ सकती है- ओपेक

नई दिल्ली। एजेंसी

नोटबंदी को 8 नंवर को एक साल पूरा हो गया है। इस पूरे एक साल के दौरान कमोडिटी बाजार पर बड़ा असर दिखा है। कारोबारियों का दावा है कि मंडियों में कामकाज अभी तक सुधर नहीं सका है। कैश कि किल्लत बरकरार है। हालांकि नोटबंदी के बाद पिछले साल सब्जियों के दाम में आई गिरावट अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। प्याज और टमाटर समेत कमोबेश सभी सब्जियों के दाम ऊपर हैं। लेकिन ज्वेलर्स का दावा है कि उनका कारोबार घटकर आधा हो गया है। ये बात अलग है कि आंकड़ों में ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले साल नोटबंदी से पहले की तिमाही में करीब 120-130 टन सोने की मांग थी, जो इस साल अप्रैल से जून तिमाही में बढ़कर 170 टन के पास पहुंच गई है। इस बीच बुधवार को सोने की चाल सुस्त नजर आ रही है। फिलहाल एमसीएक्स पर सोना 0.1 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 29450 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी 0.25 फीसदी की तेजी के साथ 39700 रुपये पर कारोबार कर रही है। कच्चे तेल में बुधवार को हल्की गिरावट आई है। हालांकि ओपेक ने कहा है कि अगले 5 साल में कच्चे तेल की डिमांड करीब 7 फीसदी तक बढ़ सकती है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक कार का चलन बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल की डिमांड पर खास असर नहीं रहेगा। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 0.75 फीसदी फिसलकर 3710 रुपये पर कारोबार कर रहा है। नैचुरल गैस 1 फीसदी गिरकर 204.6 रुपये पर कारोबार कर रहा है। जिंक को छोड़कर बेस मेटल में चौतरफा गिरावट आई है। एमसीएक्स पर कॉपर करीब 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ 443.4 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एल्युमीनियम की चाल सपाट है, जबकि निकेल 0.75 फीसदी गिरकर 820 रुपये पर कारोबार कर रहा है। लेड करीब 0.5 फीसदी गिरकर 161.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है। हालांकि जिंक 0.25 फीसदी की तेजी के साथ 208.1 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

नोटबंदी का एक साल

असंगठित क्षेत्र में 20 से 30 फीसदी तक कम हुए रोजगार

नई दिल्ली। एजेंसी

नोटबंदी के एक साल के दौरान असंगठित क्षेत्र खासा प्रभावित हुआ है। इस दौरान कई राज्यों में के अवसर कम हुए तो कई राज्यों में लोगों को छंटनी और कॉस्ट कटिंग का सामना करना पड़ा। एसोचैम के सर्वे के अनुसार 2016-17 में राजस्थान में असंगठित क्षेत्र में चार लाख से ज्यादा रोजगार आने की उम्मीद थी, लेकिन नोटबंदी के असर से असंगठित क्षेत्र में रोजगार आने तो दूर बल्कि पांच लाख से ज्यादा रोजगार प्रभावित हुए हैं।

स्टील उद्योग प्रभावित

असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान स्टील सेक्टर में ठेके पर काम कर रहे मजदूरों को भुगतना पड़ा। राज्य में लगभग 10 हजार से अधिक मजदूरों को छंटनी हई।

4 लाख से ज्यादा रोजगार प्रभावित

उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में चार लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार छिन गए। उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत उद्योग असंगठित क्षेत्र में है। नोटबंदी के बाद यहां के हालात बद से बदतर हो गए।

उत्तर प्रदेश के असंगठित उद्योगों में साड़ी उद्योग पर खासा असर पड़ा है। लखनऊ की चिकिन कारीगरी के मजदूर भी परेशान हाल हैं। कानपुर का चमड़ा उद्योग और कपड़ा उद्योग भी बदहाल स्थिति में है।

तीन बड़े राज्यों के हालात

राजस्थान के 30 फीसदी रोजगार कम हुए तो वहीं 20 फीसदी तक कारोबार पर लगा ताला। छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा कामगारों की स्टील उद्योग में हुई छटनी। वहीं एक और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 35 फीसदी कामगारों की छंटनी, इसके साथ ही साड़ी उद्योग भी बेहाल हो चुका हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के महामंत्री देवनाथ वैष्णव ने बातचीत में बताया कि,नोटबंदी के बाद अब तक के हालातों पर गौर करें तो निश्चित तौर पर कई लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा है। वहीं लघु उद्योग भारती के प्रांतीय महामंत्री पुरूषोत्तम पटेल ने कहा कि, नोटबंदी के बाद कई उद्योग और व्यवसाय को तगड़ा झटका लगा, जिसका असर सीधे तौर पर असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर पड़ा। सरकार को उन उद्योगों के प्रति नरम रवैया अपनाना होगा, जो बदहाल स्थिति में हैं, ताकि नोट बंदी के असर से पूरी तरह से बचा जा सके। ये कहना है उत्तर प्रदेश श्रमिक एवं कल्याण संघ के सचिव हरिशंकर मिश्र।

जीएसटीएन ने सिस्टम को बनाया और मजबूत, खामियों को किया गया दूरः प्रकाश कुमार

नई दिल्ली । एजेंसी

बीते साल की तमाम अस्थिरताओं के बाद जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने आज जानकारी दी है कि जीएसटी के लिए तकनीकी ढांचा तैयार करने वाली कंपनी ने टैक्स फाइल करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया है जो कि आखिरी समय में आने वाली भारी भीड़ को संभालने में सक्षम है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) जिसे 8 नवंबर 2016 को लाइव किया गया था ने इस एक साल के दौरान सिस्टम में इतने सुधार किए हैं कि यह लाखों व्यवसायों को टैक्स भुगतान और जीएसटी के अंतर्गत हर महीने रिटर्न फाइल करवाने में सक्षम हैं। कुमार ने बीते साल को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया क्योंकि इस पोर्टल पर लाखों व्यवसायों के खातें हैं जिसके जरिए ही लेन-देन किया जाना है। ये खाते नोटबंदी के बाद खोले गए थे जिसका उद्देश्य पोर्टल पर यूटिलिटीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

कुमार जो कि आईआईटी स्नातक और पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं ने बताया, 'इस तरह के प्रोजक्ट पर काम करना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहा है। जब हमने इस सिस्टम को विकसित करना शुरु किया था हमें मालूम था कि यह एक परिवर्तन लाने का मौका था। हमें एक ऐसे सिस्टम की दरकार थी जो हमें आगे ले जा सकता हो।'

आंकड़ों के हिसाब से अभी तक करीब 72 लाख व्यवसाय जो कि पहले एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट में पंजीकृत थे जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत माइग्रेट किए जा चुके हैं, जबकि 30 लाख नए व्यवसाय भी टैक्स के दायरे में आ चुके हैं।

GST परिषद की बैठक गुरुवार से

आम आदमी को मिल सकता है तोहफा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक कल से गुवाहाटी में शुरू होने वाली है। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में परिषद कई अहम फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि जीएसटी को लेकर इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा, बल्किम कारोबारियों की सहूलियत भी बढ़ेगी।

टैक्स स्लैब घटाने पर फैसला

9 से 10 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी परिषद टैक्स स्लैब घटाने पर सबसे अहम फैसला ले सकती है। इस बैठक में परिषद रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले उन उत्पादों का टैक्स रेट घटा सकती है, जो फिलहाल 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल हैं। इसमें मेकअप का सामान, इलेक्ट्रिकक बल्ब और घर के निर्माण कार्य में यूज होने वाली कई छोटी-मोटी चीजों को 18 से 12 फीसदी टैक्स रेट में लाया जा सकता है।

बाहर खाना हो सकता है सस्ता

जीएसटी परिषद की इस बैठक में कंपोजिशन स्कीम को लेकर असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह की तरफ से मिले सुझावों पर विचार किया जाएगा। मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि एसी रेस्तरां पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी कर दिया जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहले एसी होटलों पर लगने वाले रेट को घटाने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि ये रेट घटाए जाएंगे। इससे आम आदमी को बाहर भोजन करना सस्ता हो जाएगा।

बढ़ सकती है कंपोजिशन स्कीम की सीमा

कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में इसमें 1 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को ही शामिल किया गया है, लेकिन इस बैठक में इसकी सीमा 1।5 करोड़ करने पर विचार किया जा सकता है। इससे कई और कारोबार इस स्कीम के तहत आ सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्स को सकल बिक्री पर 2 की जगह 1 प्रतिशत, रेस्टोरेंट के लिए 5 की जगह 1 प्रतिशत और ट्रेडर्स के लिए 1 की जगह 0।5 प्रतिशत कर भुगतान का सुझाव दिया गया है।

आम आदमी को मिलेगी ये राहत

कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ने और होटल व मैन्युफैक्चरर्स के लिए टैक्स दर घटने से आम आदमी को भी फायदा मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारी इसका लाभ ग्राहकों तक बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो इन होटलों में लंच करना आपके लिए दूसरे होटलों के मुकाबले काफी सस्ता हो सकता है।

- घर खरीदना हो सकता है सस्ताा

इस बैठक में रियल इस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही यह संकेत दे चुके हैं। जेटली कह चुके हैं कि रियल इस्टेदट के जीएसटी के दायरे में आने से लोगों को कई तरह के टैक्सै भरने से राहत मिलेगी। इसके बाद उन्हें सिर्फ एक ही टैक्स भरना होगा। इसेस आम लोगों को घर खरीदना सस्ता पड़ सकता है।

जीएसटी की मुसीबत को लेकर मिले 700 ज्ञापन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को तार्किक व सरल बनाने के सिए सरकार की ओर से गठित 6 सदस्यों वाली सलाहकार समिति को रिटर्न दाखिल करने, ई वे बिल, इनपुट टैक्स क्रेडिट और निर्यात में उद्योग जगत को हो रही समस्याओं को लेकर 700 से ज्यादा ज्ञापन मिले हैं। सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को होने जा रही है, जिसमें इन चिंताओं पर विचार होगा। गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की महत्त्वपूर्ण बैठक के पहले समिति विभिन्न मसलों पर विचार करेगी। समिति की कुछ सिफारिशों पर जीएसटी परिषद की दिन भर होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। छह सदस्यीय समिति में उद्योग व व्यापार जगत का भी प्रतिनिधित्व है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'उद्योग जगत से जीएसटी को लेकर प्रतिक्रिया लेने और कानून की विसंगतियों को दूर करने को लेकर सरकार तैयार है। हम जीएसटी को उद्योगों के लिए मित्रवत बनाने की कवायद कर रहे हैं और सलाहकार समिति के सुझावों को शामिल किए जाने को लेकर हमारा सकारात्मक नजरिया है।' समिति अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर को देगी और उसके बाद जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। कारोबारियों के संगठन सीएआईटी के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, 'अगर समिति कुछ मसलों पर निष्कर्ष पर पहुंचती है तो हम वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अंतरिम सलाह दे सकते हैं और उसे शुक्रवार को होने वाली परिषद की बैठक में उठाया जा सकता है।' सलाहकार समिति इलेक्ट्रॉनिक वे बिल पर चर्चा करेगी और यह राय रख सकती है कि इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने के मामले में लागू किया जाए और राज्य के भीतर सामान की आवाजाही में इसकी जरूरत न हो। समिति ई वे बिल 24 घंटे के भीतर 100 किलोमीटर तक वैध होने जैसे मानकों पर भी चर्चा करेगी। समिति के एक सदस्य ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'एक खास दूरी के लिए विशेष वक्त दिया जाना थोड़ा बेतुका है।' सलाहकार समिति के सदस्य और फियो के प्रमुख अजय सहाय ने कहा कि एकीकृत जीएसटी का विस्तार निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत निर्यात के बाद के आधार पर निर्यात तक किया जाना चाहिए।

जीएसटी स्लैबों की संख्या में होगी कमी, चार से तीन स्लैब की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी को आम आदमी के लिए सरल बनाने की कवायद में सरकार दरों के स्लैब को भी कम करने की तैयारी में है। वर्तमान में जीएसटी के 5,12,18 और 28 सरीखे चार स्लैब हैं। सरकार इनमें संशोधन कर 12 और 18 प्रतिशत के दर वाले स्लैब को आपस में मर्ज करेगी।

इसके अलावा 28 प्रतिशत दर के स्लैब में केवल 5-7 लग्जरी वस्तुएं ही रह जाएंगी। इस बीच 10 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से भी बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश की चुनावी सभी में इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं।

बरकरार रहेगी 5 प्रतिशत वाली जीएसटी दर

सरकार के एक शीर्ष मंत्री के अनुसार जीएसटी के 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर बीच का एक स्लैब बनाया जाएगा, ताकि लोगों को और राहत मिले। इस कदम से जीएसटी दरों में सरलता भी आएगी। उक्त मंत्री के अनुसार 5 प्रतिशत के जीएसटी दर को बरकरार रखा जाएगा। केवल 12 और 18 प्रतिशत की दर वाले स्लैब को खत्म कर नया स्लैब बनेगा। इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा, लेकिन इस फैसले में अभी वक्त लग सकता है।

हालांकि सरकार ने इस पर राज्यों से अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी है। इसके अलावा जीएसटी के 28 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल वस्तुओं की लिस्ट बेहद कम की जाएगी। इसमें केवल लग्जरी वस्तुओं के सात-आठ आइटम ही शामिल रह पाएंगे।

जीएसटी स्लैब का अगर संशोधन मंजूर हो गया तो जीएसटी की दर तीन रह जाएगी। अभी चार स्लैब रखने के कदम का बचाव करते हुए सरकार के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि महंगाई को काबू में रखने की कवायद में जीएसटी दर के स्लैबों की संख्या 5,12,18 और 28 के रूप में रखी गई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने और टैक्स उगाही सामान्य होते ही जीएसटी दरों में बदलाव कर स्लैब को कम कर दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।

रेलवे ने लिया फैसला

बिना भूमि अधिग्रहण के कोई नई परियोजना नहीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रेलवे ने पहली बार निर्णय किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुए बिना, नई रेल लाइन बिछाने की कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। यह निर्णय इसलिए किया गया है ताकि जमीन की अनुपलब्धता के कारण कोई भी परियोजना बीच में ही ना अटक जाए। एक नई नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवहन रेलवे ने भूमि अधिग्रहण पूरा होने या एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रेलवे को जमीन देने के लिए राज्य सरकार से गारंटी का लिखित आश्वासन प्राप्त नहीं होने पर एक तरह से निविदाएं जारी करने या किसी नई परियोजना पर काम शुरू करने पर रोक लगा रखी है। नई नीति में कहा गया है, ''बोर्ड (रेलवे) ने भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही किसी नई लाइन की परियोजना को लेकर टेंडर जारी करने या काम शुरू करने का निर्णय लिया है।'' इस समय किसी परियोजना को शुरू करने के लिए केवल 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की जरूरत है जिसके चलते भूमि की अनुपलब्धता होने या निर्धारित जमीन के मुकदमेबाजी में फंसे होने के कारण अक्सर परियोजना रुक जाती है या उसमें देर हो जाती है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधिग्रहीत लाइन का रेखीय (लीनियर) होना जरूरी है। ऐसे में जब काम शुरू होता है तब समस्याएं शुरू होती हैं और आंशिक काम शुरू हो जाता है लेकिन अगले खंड के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है। एक अधिकारी ने बताया, ''इस नई नीति के अनुसार, अगर राज्य सरकार नई रेल लाइन चाहती है तो इसके लिए उसे रेलवे को भूमि उपलब्ध करानी होगी। अगर भूमि उपलब्ध नहीं होती तो हमें निवेश में नुकसान उठाना पड़ता है।'' अधिकारियों ने बताया कि हर साल ऐसे विलंब के कारण लागत में करीब 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है।

डीमॉनेटाइजेशन से तीन मोर्चों पर आरबीआई में बदला कामकाज

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

नोटबंदी के चलते आरबीआई में तीन बड़े बदलाव आए। ये बदलाव करेंसी सप्लाई, मार्केट रेगुलेशन और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के मामले में हुए है। यह सब सिस्टम से 86 पर्सेंट करेंसी हटा लिए जाने, फिर उसकी जगह पर नई करेंसी डालने और इसके चलते बैंकों में पैसा बढ़ने के कारण हुआ।

पेमेंट और सेटलमेंट का काम कैश से डिजिटल मोड में शिफ्ट होने के साथ आरबीआई के करेंसी मैनेजमेंट से जुड़े कौशल का नोटबैन के बाद के कुछ हफ्तों में इम्तिहान हुआ। रद्द किए गए नोट पब्लिक से लेकर नए नोट देने वाले कमर्शियल बैंक आरबीआई और जनता के बीच इंटरफेस की तरह काम कर रहे थे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कैश मशीनों को संभालने वालों और टेलर्स को कई बार दिन में 18-18 घंटों तक काम करना पड़ा। लॉजिस्टिक्स का मामला अहम हो गया। कैश मशीनें बेचने और मेंटेन करने वाली एनसीआर इंडिया में जनरल मैनेजर (सर्विसेज) आनंद गैरोलू ने कहा, 'दिसंबर-जनवरी के दौरान आधे से कम एटीएम चालू थे। अगले कुछ महीनों में यह आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ सका।'

आरबीआई ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया। करेंसी किसी इलाके में बड़े करेंसी चेस्ट में भेजी जाती थी और फिर वहां से आसपास के छोटे सेंटर्स पर। आरबीआई की ताजा सालाना रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने 'नोट प्रॉडक्शन के स्वदेशीकरण की कोशिश की और पिछले सालभर में नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ाए।' आरबीआई की योजना नोटों पर लगने वाली स्याही देश में ही बनाने की भी है। आरबीआई के मुताबिक, लोगों के पुराने नोट जमा करने के कारण पिछले साल 11 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच बैंकिंग सिस्टम में 4 पर्सेंट अतिरिक्त डिपॉजिट्स हुए। आरबीआई को इस अतिरिक्त लिक्विडिटी से निपटना पड़ा क्योंकि इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई। आरबीआई ने एडिशनल डिपॉजिट्स पर 100 पर्सेंट कैश रिजर्व की अस्थायी शर्त लगाकर मॉनेटरी पॉलिसी में एक अलग राह चुनी ताकि बॉन्ड मार्केट में कम से कम अवरोध आए। क्रेडिट डिमांड न होने के बीच डिपॉजिट्स ज्यादा होने के कारण कमर्शियल बैंकों ने डिपॉजिट और लेंडिंग रेट्स भी कम किए। इससे आरबीआई का काम कुछ आसान हुआ क्योंकि आरबीआई के पॉलिसी एक्शन के जरिए सिग्नल दिए बिना ही बैंकों ने कर्ज सस्ता किया।

डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन देने का दूसरा चरण जनवरी से शुरू करेगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए दूसरा चरण नए साल यानी जनवरी से शुरू करने की तैयारी में है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के तहत एक समिति जनवरी से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय भी इस योजना को अंतिम रूप देने की योजना में शामिल है। सूत्र ने बताया कि इसके लोगो और जिंगल को डिजाइन किया जा रहा है। डीएवीपी समिति की अगली बैठक एक सप्ताह में होगी जिसमें योजना सौंपी जाएगी। प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक मंत्रालय को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की अपनी योजना के साथ आगे आना चाहिए। पिछले साल नवंबर में हुई नोटबंदी के बाद से सरकार कम कैश वाली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश में है जिससे टैक्स का दायरा भी बढ़ाया जा सके।

डिजिटल होने की इतनी कीमत चुका रहे हैं आप

प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भागीदारी के कारण डिजिटल भुगतान में तेजी आई थी। आरबीआई डेटा के मुताबिक, नवंबर 2016 से सितंबर 2017 के बीच 12.13 लाख करोड़ रुपये के 933 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दिसंबर 2016 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 95.75 करोड़ तक पहुंचे जो सबसे अधिक है। अगर पैसे के लिहाज से देखा जाए तो मार्च 2017 में 1.49 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शंस हुए।

मूडीज ने बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ओबीसी की रेटिंग में सुधार किया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों - बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) - की परिदृश्य रेटिंग को नकारात्मक से सुधार कर स्थिर कर दिया है। मूडीज की ओर से इन बैंकों की परिदृश्य रेटिंग में सुधार की यह घोषणा सरकार की अगले दो साल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.1 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की बाद सामने आई है। मूडीज ने वक्तव्य में कहा है, ''मूडीज ने बैंक ऑफ इंडिया और इसकी लंदन और जर्सी शाखा के लिये परिदृश्य रेटिंग को बदल दिया है। इसी प्रकार यूनियन बैंक और इसकी हांगकांग शाखा तथा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की परिदृश्य रेटिंग को भी नकारात्मक से बदलकर स्थिर किया गया है।''

अमेरिका की इस रेटिंग एजेंसी ने इन तीनों बैंकों की स्थानीय और विदेशी मुद्रा बैंक जमा रेटिंग को भी मजबूत बताया है।

भारत में कार्यालय खोलेगी सिंगापुर की माइक्रोमनी इंटरनैशनल

नई दिल्ली। छोटे कर्ज की सुविधा देने वाली सिंगापुर की माइक्रोमनी इंटरनैशनल की अगले साल भारत में अपना कार्यालय खोलने की योजना है। कंपनी का पूरा ध्यान बैंक की पहुंच से दूर वाले बाजार और किसानों पर होगा। माइक्रोमनी इंटरनैशनल ने इस माह की शुरुआत में ही एक करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। कंपनी भारत के सूक्ष्म वित्त कारोबार क्षेत्र में अपने पांव जमाने की संभावनाएं तलाश रही है। दो वर्ष पुरानी इस कंपनी का सारा ध्यान किसानों को कर्ज देने पर है। कंपनी के सह-संस्थापक एंटन डिजीयात्कोवस्की ने कहा, हम भारतीय बाजार में पहुंच बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

मोबाइल नंबर के आधार लिंकेज पर टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने तेज की पहल

नई दिल्ली। एजेंसी

कन्ज्यूमर्स बिना रीटेल आउटलेट गए आसानी से आधार के जरिए अपने मोबाइल नंबर को री-वेरिफाई कर सकेंगे। इसके लिए टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने पहल तेज कर दी है। वह हफ्ते भर में इसके उपायों की घोषणा कर सकता है।

डिपार्टमेंट ने इस मामले में कई मीटिंग की हैं। इनमें से आखिरी मीटिंग पिछले शुक्रवार को हुई, जिसमें कंपनियों से इस पर प्रस्ताव मांगा गया। इसमें कंपनियों ने बताया है कि कन्ज्यूमर्स को री-वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा। इन प्रस्तावों को अब यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को सौंपा जा रहा है।

डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने बताया, 'यूआईडीएआई को हमने प्रोसेस के बारे में सुझाव दे दिया है। अब वह टेलिकॉम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसे अंतिम रूप देगा।' उन्होंने बताया कि टेलिकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने भी इस सिलसिले में डिपार्मटमेंट के अफसरों से मुलाकात की थी। अधिकारी ने बताया, 'हम इस हफ्ते प्रोसेस को मंजूरी देना चाहते हैं।'

इस मामले में एक बड़ी टेलिकॉम कंपनी के बड़े अफसर ने बताया कि सरकार इस प्रोसेस पर जल्द से जल्द अमल चाहती है। यहां तक कि यूआईडीएआई ने भी ट्विटर पर बताया था कि लोग आधार के तहत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) हासिल करके उसके जरिए मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकेंगे। यह काम 1 दिसंबर से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, 'प्रोसेस कंप्लीट करने में हमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इसके ट्रायल

में कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है।'

टेलिकॉम कंपनियों ने एक सुझाव दिया है कि सब्सक्राइबर्स अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक तय नंबर पर भेज सकते हैं। टेलिकॉम कंपनी इसे चेक करने के लिए यूआईडीएआई के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें देखा जाएगा कि क्या यूआईडीएआई के पास जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है, यह उससे मैच करता है? इससे री-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जो लोग ओटीपी का इस्तेमाल नहीं करना जानते, टेलिकॉम कंपनियों ने 200 रुपये चार्ज पर उनके घर जाकर वेरिफिकेशन की बात कही है। टेलिकॉम कंपनियों के प्रस्ताव की जानकारी रखने वाले एक सीनियर एग्जिक्युटिवने यह बात कही।

पिछले महीने टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एसएमएस के जरिए ओटीपी, इंटरऐक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम और टेलिकॉम कंपनियों के मोबाइल ऐप्स के जरिए री-वेरिफिकेशन की इजाजत दी थी। उसने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि लोगों को फोन कंपनियों के स्टोर के आगे लाइन ना लगानी पड़े। उसने आईआरआईएस और घर जाकर वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी मंजूरी दी है। जो लोग ओटीपी नहीं जानते या किसी वजह से फोन कंपनी के स्टोर तक नहीं जा सकते, वे इस तरह से मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि बैंक और मोबाइल फोन कंपनियां आधार से लिंक नहीं करने पर बैंक एकाउंट और फोन नंबर को डीऐक्टिवेट करने की चेतावनी दे रहे हैं। इससे लोगों में अफरातफरी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बैंकों और फोन कंपनियों की खिंचाई की थी। 12 अंकों के आधार नंबर की वैलिडिटी तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच भी बनाया है। वहीं, केंद्र सरकार ने कहा था कि सबको अपने मोबाइल नंबर को ई-केवाईसी के जरिए 6 फरवरी 2018 तक आधार नंबर से लिंक कराना होगा। उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आधार और मोबाइल फोन नंबर के लिंकेज को मंजूरी दे चुका है।

www.eng-expo.com

Organised By

FUTURE COMMUNICATIONS

- 300+ STALLS
- MORE THAN 70% SPACE OCCUPIED
- QUALITY BUSINESS VISITORS
- THE ONLY TRUSTED PLATFORM IN M.P. & C.G.
- EXPLORE THE CLEANEST CITY OF INDIA

PARTICIPATE & VISIT
in
Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO 2018

CONCURRENT EVENTS

PLAST PACK 2018
ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2018
PUMPS, VALVES & SYSTEMS EXPO 2018

INDORE | 05 - 08 JAN 2018
LABHGANGA EXHIBITION CENTRE,
Near Hotel Radisson, Before Best Price Mall, By Pass

EVENT MANAGED BY: FUTURE EVENTS
SUPPORTED BY: Indian Plastics Forum, Pumps India, Valves India, IMPA
MEDIA PARTNER: इंडियन प्लास्ट टाइम्स, ENGINEERING REVIEW, MACHINE TOOLS WORLD
DESIGN PARTNER: URBAN GRAPHICS

CALL NOW
futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com
+91 98268 87800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

पोलोग्राउंड औद्योगिक संगठन का कार्यालय प्रारंभ

इंदौर। शहर के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र पोलोग्राउंड के औद्योगिक संगठन के कार्यालय का शुभारंभ मप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बाबूसिंह रघुवंशी ने किया। इस अवसर पर उन्होनें प्रदेश में उद्योगों की स्थिती में सुधार और निवेश बढने की बात कही कार्यक्रम में विधायक रमेश मेंदोला, एआईएमपी सचिव आलोक दवे, एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ल, पार्षद दिपिका नाचन भी उपस्थित थे।

एसोसिएशन के सचिव राजकुमार हरियाणी ने बताया कि संगठन के क्षेत्र के उद्योगों के हित में कार्यालय उद्योग परिसर स्थापित किया गया है। कार्यालय शुभारंभ पर मप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बाबूसिंह रघुवंशी ने संगठन को शुभकामानाऐं दी। नए कार्यालय को सर्वसुविधा युक्त बनाया गया है। अध्यक्ष धनजय चिंचालकर ने स्वागत भाषण दिया सचिव राजकुमार हरियानी ने पोलो ग्राउंड सगठन की जानकारी दी, कार्यक्रम का संचालन संजय पटर्वधन ने किया ।

लीबिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्र शरारा पर बंदूकधारियों का हमला

त्रिपोली। एजेंसी

लीबिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्र शरारा पर सोमवार को कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। अभी हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया, 'बंदूकधारियों ने शरारा तेल क्षेत्र के स्टेशन 186 पर हमला कर दिया और वहां मौजूद स्टाफ पर भी हमला किया। इनमें से कुछ को पीटा और लूटा गया। अभी हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है।' अधिकारी ने बताया, 'तेल क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों ने हमें बताया कि बंदूकधारियों ने कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों की कमी का लाभ उठाकर हमला किया।' अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बावजूद भी तेल क्षेत्र का संचालन हो रहा है। शरारा लीबिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यहां से प्रतिदिन 270,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जो लीबिया के कच्चे तेल के उत्पादन के एक-तिहाई से अधिक है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया नए वित्त सचिव होंगे

नई दिल्ली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया को नया वित्त सचिव बनाया गया है। इस बारे में सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया। अधिया गुजरात काडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। पिछले महीने अशोक लवासा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अधिया को वित्त सचिव नियुक्त किया है। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्रालय में वरिष्ठतम सचिव को वित्त सचिव बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत पांच विभाग- व्यय, आर्थिक मामले, वित्तीय सेवा, राजस्व और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) आते हैं। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार वित्तीय सेवा सचिव हैं। वहीं, अजय नारायण झा व्यय सचिव और नीरज कुमार गुप्ता दीपम के सचिव हैं। दोनों 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1983 बैच के सुभाष चंद्र गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव हैं।

भैरवाष्टमी में करें पूजन

क्रूर ग्रह और शनि का प्रकोप होगा शांत

इस वर्ष 10 नवंबर 2017 के दिन भैरवाष्टमी मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर मतांतर से 11 नवंबर को यह मनाई जा रही है। काल भैरव अष्टमी तंत्र साधना के लिए अति उत्तम मानी जाती है। यह कठिन साधनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें मन की सात्विकता और एकाग्रता का पूरा ध्यान रखना होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान शिव, भैरव रूप में प्रकट हुए थे इसीलिए इसी तिथि को व्रत व पूजा का विशेष विधान है।

उनकी प्रिय वस्तुओं में काले तिल, उड़द, नींबू, नारियल, अकौआ के पुष्प, कड़वा तेल, सुगंधित धूप, पुए, मदिरा, कड़वे तेल से बने पकवान दान किए जाते हैं। भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं और पापी शक्तियों का नाश होता है और सभी प्रकार के पाप, ताप एवं कष्ट दूर होते हैं। इस दिन श्री कालभैरव का दर्शन-पूजन करने से शुभ फल मिलते हैं। भैरव जी की पूजा उपासना मनोवांछित फल देने वाली होती है। यह दिन साधक भैरव जी की पूजा अर्चना करके तंत्र-मंत्र की विद्याओं को पाने में समर्थ होता है। यही सृष्टि की रचना, पालन और संहारक हैं। काशी में स्थित भैरव मंदिर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाता है। इसके अलावा शक्तिपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। माना जाता है कि इन्हें स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था।

भैरवाष्टमी पूजन में करें रात्रि जागरण

भगवान शिव के इस रूप की उपासना षोड्षोपचार पूजन सहित करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए भैरव कथा और आरती करें। कालभैरव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कुत्ते को भोजन जरूर कराएं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं और भूत, पिशाच का भी डर नहीं रहता है।

क्रूर ग्रहों और शनि का प्रकोप करता है शांत

भैरव उपासना क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है। कालभैरव के राजस, तामस एवं सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होते हैं। भैरव साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए कि जाती है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं।

भैरव जी दिशाओं के रक्षक और काशी के संरक्षक माने जाते हैं। इन्हें रुद्र, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहारक भी कहा जाता है। भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है और नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व रहा है। भैरव आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट-कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। इनकी आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है, रविवार और मंगलवार के दिन इनकी पूजा बहुत फलदायी है।

कालभैरव की कृपा पाना चाहते हैं तो करें ये उपाय

भगवान कालभैरव को भगवान शिव का रूप माना जाता है। इनकी पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। भैरव को खुश करने के लिए भक्त तरह-तरह के जतन करते हैं। धर्मशास्त्रों में भी कालभैरव को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं- रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी दो रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के तीन दिन (रविवार, बुधवार व गुरुवार)। यही तीन दिन भैरवनाथ के माने गए हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद कुश के आसन पर बैठें। सामने भगवान कालभैरव की तस्वीर स्थापित करें व पंचोपचार से विधिवत पूजा करें। इसके बाद रूद्राक्ष की माला से मंत्र 'मंत्र- 'ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः'' की पांच माला जाप करें। (यह भी पढ़ें: जन्म के साथ ही यहां कालभैरव को कराया जाता है मदिरा पान) ऐसे भैरव मंदिर में जाएं, जहां कम ही लोग जाते हों। वहां जाकर सिंदूर व तेल से भैरव प्रतिमा को चोला चढ़ाएं। इसके बाद नारियल, जलेबी आदि का भोग लगाएं। याद रखिए अपूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं।

देश में ई-व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही शुरू करने के लिए कहा है। सीनियर अफसरों ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्टोरेज से जुड़ी पॉलिसी बनाने के लिए ग्लोबल मार्केट्स की स्टडी कर रही है। सरकार के एक सीनियर अफसर ने ईटी को बताया, 'हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स अपना प्लांट भारत में लगाएं। हमने बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं और उनका भविष्य स्टोरेज कैपेसिटी में छुपा है।'

पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने पिछले महीने ही कहा था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मीटिंग बुलाई है और उनसे इन सेक्टर में निवेश की शुरू करने के लिए कहा है, जहां भविष्य उज्ज्वल है। आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काम कर रहे हैं। हम इसमें सपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाने पर भी काम करेंगे। हमने कई स्टेकहोल्डर्स के साथ डिस्कशन शुरू किया है। हम सही समय पर सही तरह की पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे।'

सरकार ने ऐसे चुनिंदा अहम क्षेत्रों की पहचान की है, जिनसे ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सकता है। एक अन्य सरकारी

अफसर ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, 'चर्चा इस बात पर केंद्रित रही थी कि कैसे इस फील्ड की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रेरित किया जाए, स्टोरेज को किस तरह समय के साथ अपग्रेड किया जाए कि बैटरियों का इंपोर्ट बंद हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को किस पॉलिसी की जरूरत है जिससे चार्जिंग स्टेशंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिले।' मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित हैं लेकिन उनके लिए सरकार के पास फिलहाल कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'फिलहाल कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। आप ही देखिए कि इंडिया में 1.3 अरब लोग हैं और हमें कैसे वाहनों की जरूरत है और हमें कैसी रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज चाहिए। यहां इतने बड़े पैमाने पर कारोबार की संभावना है कि यह मार्केट अपने आकर्षक हो जाता है।' हालांकि इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि उससे बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बने। आधिकारिक सूत्र ने कहा कि कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने को तैयार हैं और सरकार भी इससे जुड़े प्रोसेस में तेजी लाने पर काम कर रही है। पावर मिनिस्टर की मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली और स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइडर्स दिग्गज नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में उठने वाले सरकार के कदमों की अगुवाई सरकारी थिंकटैंक नीति आयोग करेगा। आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'इस सेक्टर में स्टेकहोल्डर्स बहुत हैं इसलिए इसकी अगुवाई नीति आयोग इस इस तरह करेगा कि संबंधित मंत्रालयों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित और समन्वित हों।'

हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड में बदलाव चाहते हैं ज्वैलर

नई दिल्ली। एजेंसी

जनवरी से सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की सरकार की योजना से बुलियन बाजारों में हलचल देखी जा रही है। आमतौर पर ज्वैलर हॉलमार्किंग स्कीम के विरोध में नहीं दिखना चाहते, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्म्स को लेकर असंतोष जता रहे हैं। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सरकार अब 14,18 और 22 कैरेट की सिर्फ तीन कैटेगरी में सोने की हॉलमार्किंग को मान्यता देगी, जबकि ज्वैलर चाहते हैं कि उसमें 20 कैरेट को भी शामिल किया जाए। वे ज्वैलर्स को लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और फीस से मुक्त करने की मांग भी कर रहे हैं।

बीआईएस आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अभी तक करीब 700 ज्वैलर ही हॉलमार्क लाइसेंसी हैं, जो कुल तादाद का 10 पर्सेंट भी नहीं है। ऐसे में दो महीने के भीतर सभी ज्वैलर्स को बीआईएस कंप्लायंस के दायरे में लाना आसान नहीं होगा।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एस के जैन ने बताया कि सरकार लंदन बेस्ड हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड अपनाने जा रही है, जिसके तहत सिर्फ 14,18 और 22 कैरेट के हॉलमार्क्ड स्वर्ण उत्पाद बिक सकेंगे। लेकिन यह भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के लिहाज से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 14 कैरेट सोना 58.33% शुद्धता का होता है, जो जड़ाऊ गहने बनाने में काम आता है और जिनकी चुनिंदा शहरी ग्राहकों में मांग है।

जैन ने कहा कि 18 कैरेट 75% शुद्धता का मानक है, लेकिन भारत में बदलते जलवायु और समय के साथ इस शुद्धता के गहनों की रंगत फीकी पड़ जाती है और ज्वैलर्स की विश्वसनीयता घटती है। 22 कैरेट का सोना 91.60% शुद्ध होता है, लेकिन उससे टिकाऊ जेवर बनाना मुश्किल होता है। ज्यादातर छोटे और मझोले ज्वैलर ग्राहकों की मांग के हिसाब से 80-85% शुद्धता वाले गहने बनाते हैं। ऐसे में सरकार को रिवाइज्ड हॉलमार्किंग मानकों में 20 कैरेट (83.33%) को शामिल करना चाहिए। कूचा महाजनी वाले द बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल ने बताया, 'हम हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन यह तभी सफल हो पाएगी, जब ज्वैलर्स को लाइसेंसिंग, फीस के बोझ और रेडराज से मुक्त रखा जाएगा।' उन्होंने कहा कि सरकार को हॉलमार्किंग अनिवार्य करने से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना चाहिए और हॉलमार्किंग सेंटर्स की तादाद बढ़ाना चाहिए। किसी ज्वैलरी में कोई खामी पाई जाने पर उसके लिए ज्वैलर नहीं हॉलमार्किंग सेंटर को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। सिंघल ने आशंका जताई कि हॉलमार्किंग की कानूनी अनिवार्यता होने के बाद अधिकारी ज्वैलर्स को सोने की शुद्धता से ज्यादा छोटी मोटी कागजी चूक के लिए भी परेशान कर सकते हैं। हॉलमार्किंग फीस शहर और टर्नओवर के हिसाब से 1000 से लेकर 20,000 रुपये तक है।

महिंद्रा एक्सयूवी 500 का पहला पेट्रोल वैरियंट, जी9 पेट्रोल जल्द होगा लॉन्च, जीप कम्पस से होगा मुकाबला

नई दिल्ली। एजेंसी

महिंद्रा अपनी पेट्रोल इंजन वाली नई एक्सयूवी 500 एसयूवी को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसमें 2.2 लीटर मोटर लगा होगा जो कि 140 बीएचपी का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करने में मदद करेगा। इस इंजन को डीजल इंजन के ब्लॉक पर ही तैयार किया जाएगा। महिंद्रा XUV 500 पेट्रोल वैरियंट लाइनअप में 'G' से नामकरण होगा, जबकि डीजल इंजन की एसयूवी में 'डब्ल्यू' है। फिलहाल, शुरुआत में महिंद्राXUV500 का एक ही पेट्रोल वैरियंट, G9 लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा। नई महिंद्रा XUV500 G9 में टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा लेकिन इसमें लेदर सीटें मिसिंग हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसमें अलॉय वील्ज भी नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें दो एयरबैग्स दिए जा सकते हैं। नई XUV500 पेट्रोल इंजन एसयूवी का मुकाबला जीप कम्पस पेट्रोल से होगा जो कि 1.4 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है।

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सीधे वित्त मंत्रालय से आई ये बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक सैलरी हाइक मिलेगी। सैलरी में होने वाली बढ़ोत्तरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि सरकार नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के समय में महंगाई एक जरूरी मुद्दा है और केन्द्रीय कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। वो लोग जो सातवें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, उनमें कुंठा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है।

ये कहा एनएसी ने अधिकारियों का कहना है कि सरकार एनएसी की सभी सिफारिशों को मान लेगा। सूत्रों के अनुसार अरुण जेटली ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी और वह अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। सैलरी हाइक की घोषणा करने से पहले कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। एनएसी ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की स्थिति और सैलरी हाइक से सरकार पर बढ़ने वाले बोझ को भी ध्यान में रखना होगा।

21,000 होगा न्यूनतम वेतन सरकारी सूत्रों ने इस बात की काफी पहले ही पुष्टि कर दी है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपए करने का फैसला किया गया था।

न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार इसे 21 हजार रुपए करने पर विचार कर रही है।

नहीं मिलेगा एरियर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी, लेकिन किसी को भी एरियर नहीं देगी। यह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरियर क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरियर दे देती है तो केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरियर नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 25,000 करने पर ही केन्द्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।

Organized by
PLASTINDIA FOUNDATION®
ISO 9001-2008 certified

PULSE of PLASTICS – PLASTINDIA

OVER 50,000 VISITORS HAVE ALREADY REGISTERED ONLINE
FOR THE THIRD LARGEST EXHIBITION IN THE WORLD FOR PLASTICS INDUSTRY
ORGANISED BY THE PLASTICS INDUSTRY

125,000 sq mtrs of total exhibition area
2000 of the world's finest exhibitors
500+ overseas exhibitors from 40 countries
200,000 visitors from all over the world

LOG ON TO www.plastindia.org OR DOWNLOAD THE MOBILE APP.

PLASTINDIA 2018
EMPOWERING GROWTH
10th International Plastics Exhibition, Conference & Convention
Feb. 7-12, 2018, Gandhinagar - Ahmedabad, Gujarat, India.

ufi Approved International Event

401, Landmark 'B', Suren Road, Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, India.
Tel.: +91-22-26832911 / 14 • Fax: +91-22-26845861 • E-mail: info@plastindia.org

CONCURRENT EVENTS: PROPLAST – The final word in processed plastics | Plasticon Awards 2018 – Recognising Excellence | 10th International Conference | MEET 2 TRADE

Supported by: Government of India, Government of Gujarat, INDEXTb, Make in India
Exclusive Overseas Associates: Messe Düsseldorf, ADSALE, Plastic International
Supported by: EUROMAP

www.againsttheflow.in - +91 9820708887

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।